

प्रेषक,

डी0एस0 गर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक | १ फरवरी, 2016

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरपालिका परिषद, कर्णप्रयाग को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, कर्णप्रयाग के पत्रांक-मैमो/दिनांक 15.09.2015 एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, कर्णप्रयाग के पत्रांक-231/अव0/2015-2016, दिनांक 10.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, कर्णप्रयाग द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹ 115.99 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹ 65.99 लाख (रूपये पैसठ लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमोदित लागत	प्रथम किस्त में स्वीकृत
1.	नये बस अड्डे में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य।	103.17	53.17
2.	हिल साईड सिमली रोड, कर्णप्रयाग में पार्किंग निर्माण कार्य।	12.82	12.82
योग-		115.99	65.99

2- उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :-

- I. उक्त धनराशि कुल ₹ 65.99 लाख (रूपये पैसठ लाख निन्यानवे हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, कर्णप्रयाग (चमोली) को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- II. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणारों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- III. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- V. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- VI. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- VII. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- VIII. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपर्युक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- IX. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राज्यकोष में जमा करा दी जाये।

X. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

XIII. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIV. धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास—'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0— 1051/XXVII(2)/2016, दिनांक 10.02.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-5/1602/2038/ के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्वाल)
सचिव।

संख्या—3/2(1)/IV(2)-श0वि0—2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, माओ मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, कर्णप्रयाग।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0एस0 राणा)
उप सचिव।